Schools without Buildings in Backward and Adivasi Areas

*245. SHRI R. V. BADE: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of schools running without buildings in backward and Adivasi areas in the country; and

(b) the amount Central Government propose to grant to the States earmarking them for buildings for Schools?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL (SHRI RAM NIWAS MIRDHA): (a) Information is not readily available.

(b) There are no special earmaked grants for this purpose under the Centrally Sponsored or Central Sector Scheme. However, under the Tribal Development Block Programme, 12 per cent of the annual outlay is to be spent on educational and allied schemes which include construction of buildings. Moreover, under the scheme of providing Employment to the Educated Unemployed—Expansion of Elementary Education of the Ministry of Education, funds have been provided to the State Governments, among other things, for the construction of classrooms. This scheme will benefit the backward and tribal areas also.

श्री आर० वी० बडे: आप ने लिखा है कि There are no special ear-marked grants. क्या शासन भविष्य में ईयर-मार्कड ग्रान्टस करना चाहता है कि इतना पैसा बिल्डिगों पर खर्च किया जायगा ? क्या इस प्रकार की कोई प्रस्तावना है ?

श्री रामनिवास मिर्धा : मकानों पर पैसा कम खर्च किया जाय और दूसरी मदों पर ज्यादा खर्च किया जाय-इस प्रकार की राज्य सरकारों की नीति प्रतीत होती है । राज्य सरकारों को शिक्षा के सम्बन्ध में ब्लाक-लोन्ज या ग्रान्ट्स दी जाती हैं, उस में से कितना भवन के लिए खर्च करे और कितना अध्यापकों के लिए खर्च करें, वे सरकारे अपनी परिस्थितियों को देखते हुए अपनी विभिन्न नीतियां बनाती हैं । केन्द्रीय सरकार प्राथमिक-शालाओं के लिये विशेष अनुदान दे ऐसी सरकार की नीति नहीं है ।

श्री आर० वी० बडे : आप ने कहा था कि 12 परसेंट हर एक स्टेट को दिया जाता है शिक्षा के लिए । क्या मंत्री जी को मालूम है कि जहां जहां 12 परसेंट पैसा दिया जाता है, वह सब टीचरों की एपाइन्टमेंट पर खर्च हो जाता है, उस धनराशि का 25 परसेंट भी भवनों के निर्माण पर खर्च नहीं होता है । जिस का परिणाम यह होता है कि बच्चे पेड़ों के नीचे बैठ कर पढ़ते हैं । क्या आप राज्य सरकारों से कहेंगे कि इस धनराशि में से इतनी धनराशि बिल्डिगों के निर्माण पर खर्च की जाये ?

श्री रामनिवास मिर्धा : राज्य सरकारों को इस बात के लिए बाध्य करना कि अमुक पैसा आप मकानों पर अवश्य खर्च करें ऐसी सरकार की नीति नहीं है । माननीय सदस्य ने जो स्थिति बतलाई है, वह सही है, बहुत से स्कूल ऐसे हैं, विशेष तौर से पिछड़े क्षेत्रों में, जहां पाठशालाओं के भवन नहीं हैं । लेकिन हम यह उचित समझते हैं कि राज्य सरकारें स्वयं महसूस करे कि कितना पैसा वे अध्यापकों पर खर्च करें और कितना मकानों पर खर्च करे ।

SHRI D. BASUMATARI: While replying to Mr. Bade, the hon. Minister referred to the tribal development blocks. The tribal development blocks are located in areas which are predominantly inhabited by the tribals, more than 65 per cent of the population are tribals. The Minister said that the responsibility lies with the States. I do not understand why the responsibility does not lie with the Centre because money is being spent by the Centre on these tribal blocks.

May I know whether there is any machinery with the Government to find out whether the monies sanctioned by the centre are properly utilised for the development of education in the tribal blocks because you spend large sums of money to promote the educational development?

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: The hon. Member has raised a such wider question of utilisation of funds on tribal development blocks by the State Governments. We have various ways of checking whether the funds have been properly spent or not and we do hope that in most cases they are properly spent and the State Governments are really keen that the tribal development blocks are successful.

श्री नरसिंह नारायण पांडे : क्या भवन निर्माण के सम्बन्ध में कोई योजना आप के विचाराधीन है ? क्या आप यह भी विचार करेंगे कि पांचवी पंचवर्षीय योजना में स्कूलों के डवलपमेंट के लिए, बैकवर्ड एरियाज में और ट्राइबल एरियाज में अधिक से अधिक प्राइमरी स्कूल बन सकें ? खास कर जहां पेड़ों के नीचे या खले आसमान के नीचे बच्चे पड़ रहे हैं, उन के लिए कोई विशेष व्यवस्था करेंगे ?

श्री रामनिवास मिर्धा : इस प्रोग्राम में जो प्रावधान है, उस में जो कार्य लिये जा सकते हैं, उन में भवन निर्माण का कार्यक्रम भी है। अब कितना भवन पर खर्च करें, कितना दूसरे कार्यक्रमों पर खर्च करें, यह राज्य सरकारों पर निर्भर करता है। इस के लिए कोई केन्द्रीय आदेश जाय मैं समझता हूं हमारी जो योजना बनाने और कार्यान्वित करने की पद्धति है, यह उस के अनुकूल नहीं होगा।

श्री मोहम्मद इस्माइल : मंत्री महोदय के वक्तव्य से यह बात साफ़ हो चुकी है कि ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिस के जरिए राज्य सरकारों को कहा जाय कि इतना रुपया बिल्डिंग पर खर्च करो। हमें तमाम प्रान्तों से खबर मिली है और यह सही बात है कि जितना पैसा मिलता जाता है, वह बिल्डिंगों पर खर्च नहीं होता है। इस लिए मैं पूछना चाहता हूं क्या आप कोई ऐसी नीति बनाने जा रहे हैं जिस के जरिये आप डायरैक्शन दें कि इतना इतना फन्ड बिल्डिंगों के लिए रिजर्व कर दिया जाय और अनुसूचित जातियों के लिए स्कूलों की बिल्डिंग्ज जरूर बनाई जांय ?

श्री रामनिवास मिर्धा : मैं पहले भी बतला चुका हूं हम नहीं चाहते कि इस में निश्चित रूप से राज्य सरकारों को कुछ कहा जाय। वे जैसा उचित समझते हैं भवनों पर पैसा खर्च करते हैं।

SHRIMATI M. GODFREY: One of the needs in our country is education besides food. Will the Minister consider improving the lot of the schools, particularly, in the backward areas? As the Government considers beautifying the cities, environmental conditions for children should also be made conducive so that children would really like to stay in the schools and get an all-round education.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: I am completely in agreement with the sentiments—expressed by the hon. Member. But the point is this. To provide buildings for all the new enrolments during the fifth plan and also to provide buildings to such of the existing schools as have no buildings of their own would cost us about Rs. 1,000 crores and with the limited resources available we have to see how much to spend on buildings, how much on teachers and how much on educational facilities.

श्री रामसिंह भाई वर्मा : श्रीमन्, अर्थाभाव के कारण बिल्डिंग्ज का इंतजाम पूरा नहीं हो पाता तो क्या राज्य सरकारों को यह आदेश देंगे कि ऐसी अवस्था में गर्मियों की छुट्टियां न रखकर बरसात में छुट्टियां रखी जाये और गर्मियों में पढ़ाई की जाये ?

श्री राम निवास मिर्धा : राज्य सरकारों ने गर्मी और सर्दी की छुट्टियों के बारे में अपनी परिस्थितियों को देखते हुए विभिन्न योजनायें बनाई हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह सुझाव अच्छा है, आप विचार करिये ।

श्री राम निवास मिर्धा : यह तो कई राज्यों में हो भी रहा है । स्थानीय परिस्थिति के अनुसार राज्य सरकारें छुट्टियों की व्यवस्था करती है । माननीय सदस्य का यह सुझाव भी बहुत उचित सुझाव है और वे अवश्य इस पर विचार करेंगी ।

SHRI P. GANGADEB: In view of the fact that adivasis form an important and significant part of the population in Orissa State may I know from the Government whether Government is thinking of taking any special steps under President's rule to promote building construction in respect of schools, hospitals and other amenities and if so, what are the broad details thereof?

MR. SPEAKER: Ultimately everyone's question revolves round the first question in different form. The answer may be also given in different shapes, but the information is the same. I have no objection if the Minister wants to answer.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: In view of the fact that Orissa is under the President's rule, he wants to know about the special steps which are being taken. If he puts a specific question, I will answer it.

SOME HON. MEMBERS—*rose.*

MR. SPEAKER: There are certain Members who are permanently on their legs. Shri S. B. Giri.

SHRI S. B GIRI: The hon. Minister has said that apart from the grant for construction of buildings, there are other types of grants like scholarships to the students of the tribal people and the backward class people.

MR. SPEAKER: Mr. Giri, scholarship will arise only if the building is there.

SHRI S. B. GIRI: I am talking about those who are already studying. In view of the fact that there are more number of students among the tribal people and also backward class, may I know whether the Central Govment is intending to increase the grants to these States where these tribal people and backward class people live, in respect of these States which have already sent in their demands?

MR. SPEAKER: I invite the hon. Member's attention to the fact that I must also satisfy myself about the relevancy of the question. This question has not got much relevance. But I do not mind if the Minister is ready to reply. I do not want to come in his way.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: We have one important scheme for scholarships which is for post-metric scheduled caste and scheduled tribe students. The present quantum of scholarships is very inadequate and it was fixed long time back. The hon. Prime Minister herself has mentioned that it should be increased. We have taken it up with the Planning Commission that the quantum of scholarship should increase by fifty per cent at least.

SOME HON. MEMBERS—*rose.*

MR. SPEAKER: This question has taken so much time arleady and yet so many hon. Members are getting up. I am so sorry. Shri Ramavatar Shastri.

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, सरकार कहती है कि वह आदिवासी इलाके में विशेष विकास की व्यवस्था करना चाहती है तो फिर उनके लिए विशेष रुप से शिक्षा की व्यवस्था की जाये जिसमें भवन निर्माण

का भी काम हो उसमें कौन सी कठिनाई है ? अब आप विशेष सहुलियत दे रहे है तो शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्हे विशेष सहूलियत दी जाये उसके रास्ते में आपके सामने क्या कठिनाई है ?

श्री राम निवास मिर्धा: कठिनाई केवल साधनों की है इसलिय ज्यादा पैसा अध्यापकों पर खर्च किया जाये या स्कूलों के कमरे बनाने पर खर्च किया जाये यह सवाल आता है । इसलिए यह निर्णय किया जाता है कि कितना पैसा किस पर खर्च किया जाये उसका स्थानीय प्रशासन ही निर्णय करे ।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के उत्तरों से इस मामले में कुछ लाचारी मालम होती है लेकिन में उनका ध्यान संविधान की दफा 164 की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसकी तहत विहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के लिए एक विशेष मंत्री होता है और उसी तरह से दफा 339 की तहत निदेश देने का अधिकार दिया हुआ है मेरे अपने क्षेत्र के बारे में, मैं जानता हूं कि आदिवासी गांवों में भवनों का पता नहीं है तो क्या सरकार कम से कम तीन राज्यों में जहां ट्राइबल वेलफेयर के लिए अलग मंत्री होता है उनको पत्र लिखेंगे जिससे भवनों के निर्माण के काम पर भी कुछ पूंजी लगाई जाये, कुछ ज्यादा पसा उस पर खर्च किया जाये ?

MR. SPEAKER: It is a suggestion for action.

श्री मधु लिमये : मैं ने स्पष्ट पूछा है क्या पत्र लिखगे ।

श्री रामनिवास मिर्धा : यह प्रश्न सरकार की संवैधानिक लाचा ी का नहीं है वल्कि क्या हमें इस मसले में कोई आदेश देना चाहिए या नही, यह नीति का प्रश्न है । और भी बहुत सी बातें हैं जिस पर आदेश दिये जा सकते हैं, भवन भी उसमें हो सकते हैं लेकिन हमने यह उचित समझा कि जैसे ट्राइवल डेवलपमेन्ट ब्लाक्स हैं उसमें उनको कार्यक्रम दिया जाता है, विशेष मद होती है जिन पर पैसा खर्च होता है और राज्य सरकारें कितना किस मद पर खर्च करें शिक्षा के क्षेत्र में यह उन पर छोड़ा जाता है और मैं समझता हूं यह उचित ही है ।

Separatist Campaign in Tamil Nadu

+

*246. SHRI RAMAVATAR SHASTRI:
SHRI PURUSHOTTAM KAKODKAR:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the press reports regarding Shri E. V. Ramaswami Naicker's Separatist Campaign in respect of Tamil Nadu;

(b) if so, whether Government of India have taken up the matter with the Tamil Nadu Government;

(c) if so, with what result; and

(d) Government of India's reaction to such a campaign?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOHSIN): (a) and (b). Yes, Sir. The Government of Tamil Nadu have been requested to examine the feasibility of initiating legal action.

(c) and (d). Reply from the Government of Tamil Nadu is awaited.

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, हमारे देश के कानून के अनुसार देश के बटवारे की बात करना देशद्रोह माना जाता है । इसलिए में यह जानना चाहूंगा कि आपने अभी कहा कि वहां की सरकार को लिखा गया है, तो कब लिखा गया और उसके बाद फिर तमिलनाडु सरकार से इस बात में शीघ्रता